Title: Regarding Government Business during the week commencinng on 2nd May, 2000.

12.08 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing the 2nd May, 2000 will consist of: -

1. Discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Ministry

   of Human Resource Development.

2. Submission to the Vote of the House outstanding Demands for Grants in

   Respect of Budget (General) for 2000-2001 at 6 p.m. on Tuesday the 2nd May, 2000.

3. Consideration and passing of the Finance Bill, 2000.

4. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, we have raised an important issue. The hon. Member is present here. Let him clarify the position. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajesh Pilot, we have to complete the Submissions now. The hon. Minister of Parliamentary Affairs has announced the programme for the next week. Hon. Members have given notices to make their Submissions. That has to be taken up now.

...(*Interruptions*)

श्री रामजी लाल ्सुमन (फिरोजा्बाद) : उपाध्यक्ष महोद्य, लोक ्सभा की आगामी ्सप्ताह की कार्य ्सूची में निम्न व्ि्यों को ्सम्मिलित कि्या जाए।

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों का ्सरकार द्वारा ्समुचित ्संरक्षण देने पर व्िचार -

जि्स्से ्भारती्य अर्थव््यव्स्था को पटरी पर ला्या जा ्सके।

2. परम्परागत उद्योगों जै्से फिरोजा्बाद का कांच उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, मुरादा्बाद का

पीतल के ्बर्तनों का उद्योग एवं ्वाराण्सी के ्सिल्क उद्योग को उचित ्सरकारी ्संरक्षण देने पर

व्िचार।

श्री रा्सा ्सिंह रा्वत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोद्य, कृप्या आगामी ्सप्ताह की कार्य्सूची में निम्न व्ि्यों को ्सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. कि्शनगढ़ और ्ब्या्वर जै्से अजमेर जिले के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व््यापारिक महत्व के ्शहर दिल्ली-अहमदा्बाद ्वा्या ज्यपुर अजमेर रेल्वे लाइन पर ्स्थित हैं, ्वर्तमान में ्यहां आश्रम एक््सप्रै्स (सुपरफा्स्ट) तथा अन्य लम्बी दूरी की गाड़ि्यों को दो मिनट का ्स्टापेज दि्ये जाने की आ्व्श्यकता।

2. नई दिल्ली-अजमेर ्शता्ब्दी को इ्सकी आ्व्श्यकता एवं उप्योगिता को ध््यान में रखकर ्सप्ताह के कि्सी और दिन ्बन्द रखकर र्व्िवार को ्भी चला्ये जाने की आ्व्श्यकता। धन््यवाद।

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Sir, the following item may be included in the next week's agenda:

'New monetary and credit policy of the Reserve Bank of India.'

SHRI E. AHAMED (MANJERI): I would like to make a submission for the agenda for the next week.

"That a comprehensive legislation to the Central Haj Act should be introduced in the current Session to replace the redundant Central Haj Act, 1954. "

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include the following subjects in the Business of the next week.

1. For 714 items quantitative restrictions are removed from April, 2000. Further 715 items will be opened from April 2001. Exim Policy, WTO commitment must be discussed keeping in mind, the future of Indian industries, particularly small-scale industries.

2. Continuous fall of growth rate of agriculture production in the nineties compared to eighties must be discussed. Growth rate of agriculture production is coming down compared to population growth. This matter is of grave concern.

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विय जोडे जाएं।

1. मध्य प्रदेश में स्थापना व्यय के बढ़ते जाने से प्रदेश के विकास के लिए धनराशि की कमी पर चर्चा।

2. मध्य प्रदेश की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की मरम्मत व रख-रखाव प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपने के फलस्वरूप धनाभाव में नल योजनाओं के बंद हो जाने से पेयजल के गंभीर संकट पर चर्चा।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न वियों को सम्मिलित किया जाए ।

1. एच.ई.सी. हटिया, रांची जो मदर इंडस्ट्रीज कहलाता है, कार्यदेश न मिलने से मजदूरों का भविय अंधकार में हो गया है। इस विभाग को रक्षा, रेल, कोयला आदि मंत्रालयों से अधिक से अधिक कार्यादेश दिलाया जाए। विस्थापित एवं विधवा आश्रितों के परिवारों को नौकरी दिलाई जाए और कर्मचारियों को बिजली आदि अन्य सुविधाएं दी जाएं।

2. रांची शहर जिसकी आबादी लगभग 15 लाख है, अभी तक नेशनल हाई वे पर बाई पास सड़क नहीं बनी है, जिससे शहर में सड़क दुर्घटनाएं एवं सड़क जाम बराबर होता रहता है। अत: रांची शहर का बाई पास सड़क का निर्माण अविलंब कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

डा.सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, 550 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने के बाद फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकोनोमिक कास्ट 900 रुपये हो जाना कदापि न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। एफ. सी.आई. के बढ़े खर्चे के कारण देश में गेहू का उत्पादक कम कीमत मिलने से परेशान है तो दूसरी ओर उपभोक्ता बेतहाशा बढ़े मूल्य पर खरीदने को मजबूर हैं एवं दुखी है। कैसी विडम्बना है कि कनाडा, ब्राजील, आस्ट्रेलिया में भारत की तुलना में गेहू की उपज दर कम होने के बावजूद वे देश भारत के कम मूल्य पर अन्तर्राट्रीय बाजार में गेहूं बेच रहे हैं। अत: एफ.सी.आई. के सम्पूर्ण कार्यकरण तथा क्रियाकलापों की विस्तार से चर्चा आवश्यक है।

...(*Interruptions*)